राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 10842/2021

बंशी लाल बागोरा पुत्र स्वर्गीय श्री महेश कुमार बागोरा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम मनपर्दा, पोस्ट कुआ, तहसील चिखली, जिला-डूंगरपुर---याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, डूंगरपुर---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री रामदेव पोटालिया।
प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः-

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

10/01/2024

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के खिलाफ एक निर्देश की मांग करता है कि वे कि वे अनुकंपा के आधार पर तृतीय श्रेणी के लिए उसके दावे पर विचार करें और उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बजाय एलडीसी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

2. पहले संक्षिप्त तथ्यात्मक वर्णन करें।

2.1. यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के पिता, श्री महेश कुमार, प्रतिवादी विभाग में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और 09.04.2017 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी विभाग को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने अन्य दस्तावेजों के साथ 14.09.2017 को जारी अपना बीएपी प्रमाण पत्र भी जमा किया।

2.2. याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद, उन्हें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेमलिया घाटा में दिनांक 25.06.2018 के आदेश द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 29.06.2018 को ज्वाइन किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुकंपा के आधार पर एल. डी. सी. के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के बावजूद, उन्हें वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा से बी. ए. पी. योग्यता (उच्च माध्यमिक) होने के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। हालाँकि, इस योग्यता के आधार पर, याचिकाकर्ता ने और भी उच्च योग्यता प्राप्त कर ली है, जिस पर विचार नहीं किया जा रहा है। उत्तरदाताओं को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बजाय एल. डी. सी. के पद के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना चाहिए। इसलिए यह याचिका लगाई गई है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं।

4. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि याचिकाकर्ता की साख को देखते हुए उन्हें एल. डी. सी. नियुक्त किया जाना चाहिए था। भले ही यह माना जाता है, हालांकि विभाग द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है, कि उसके पास उच्च माध्यमिक

शिक्षा थी, वह अपनी शिक्षा के अनुरूप अधिकार के रूप में एल. डी. सी. के पद पर श्रेणी-III के कर्मचारी के रूप में पद का दावा नहीं कर सकता है।

5. यह ध्यान रखना उचित है कि अनुकंपापूर्ण नियुक्तियां सेवा में आरक्षण के रूप में प्रदान नहीं की जाती हैं। इसके बजाय, उन्हें सेवा में मरने वाले कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा परोपकार के संकेत के रूप में पेश किया जाता है।

6. यह स्वाभाविक है कि किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु परिवार के लिए वित्तीय आपदा का कारण बनती है, जिससे वे पूरी तरह से गरीबी में चले जाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान ऐसे परिवारों के सामने आने वाले तत्काल वित्तीय संकट को कम करने के लिए है।

7. अनिवार्य रूप से अनुकंपापूर्ण नियुक्तियां आवेदक की शिक्षा के अनुरूप नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पर्याप्त होनी चाहिए, जो एकमात्र कमाने वाला था।

8. मुझे प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता। हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. तदनुसार इस रिट याचिका को बर्खास्त किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।